

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

दोस्रो संख्या 24/2020, जी.सी.एम.एस. नं. 2020/00056

1. बजरंगा पुत्र कुन्जा
2. बाबू पुत्र कुन्जा
3. मुरारी पुत्र बजरंगा
4. राधेश्याम पुत्र बजरंगा
5. हरबाई पत्नी पप्पू
6. रामबाई पत्नी मोहनलाल

समस्त जातियान बैरवा निवासीयान पनियाला तहसील  
मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर।

अपी०

बनाम

1. गंगाधर पुत्र कुन्जा
2. सोन्या पुत्र कुन्जा
3. मोहन पुत्र कुन्जा
4. माया पत्नी मुरारी
5. इन्द्रा पत्नी राधेश्याम
6. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा मलारना डूंगर
7. तहसीलदार मलारना डूंगर।

समस्त जातियान बैरवा निवासीयान पनियाला तहसील  
मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर।

रेस्पो०

(अपील विरुद्ध निर्णय न्यायालय उपजिला कलेक्टर मलारना डूंगर मु०न० 48/2018  
निर्णय दिनांक 05.12.2019)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांट की ओर से श्री राधेश्याम वैष्णव
2. रेस्पो० की ओर से श्री राकेश कुमार सैनी एवं नन्द किशोर बैरवा

निर्णय

दिनांक 29.03.2020

1. प्रस्तुत अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम 1955) के तहत मु०न० 48/2018 निर्णय दिनांक 05.12.2019 न्यायालय उपजिला कलेक्टर मलारना डूंगर के विरुद्ध पेश की गई है। अपील के तथ्य

संक्षेप में इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में सायलान/रेस्पों. की ओर से एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटी0एक्ट का इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि आराजी खाता सं. 39 ख.नं. 177 रकबा 0.0200 है0, ख.नं. 487 रकबा 0.1400 है0, ख.नं. 493 रकबा 0.8600 है0 है जो सायलान व गैरसायलान 1 ल0 4 के संयुक्त खातेदारी की आराजी है जिसमें सायलान का 1/5 हिस्सा है जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त विवादित आराजी को सायलान व गैरसायलान सं. 1 ल0 4 अपने-अपने हिस्से पर काश्त करते चले आ रहे हैं और फसल लाभ ले रहे हैं। दिनांक 07.07.2018 को सायलान अपने हिस्से की आराजी ख.नं. 493 रकबा 0.8600 है0 पर फसल काश्त कर रहा था तो गैरसायलान सं. 1 ल0 10 व उनके परिवार वाले सभी लोग मौके पर लाठी डण्डे लेकर आ गये और फसल को पलट दिया और सायलान के हिस्से 1/5 पर काश्त में माने मजाहमत करने व भविष्य में काश्त नहीं करने की ऐलानियां धमकी दी। सायलान ने तहसील कार्यालय चलकर खाते छटवाने की बात कही तो गैरसायलान ने साफ इन्कार कर दिया व मारपीट पर आमदा हो गये तथा जान से मारने की धमकी दी। इसकी रिपोर्ट थाना मलारना डूंगर में दर्ज करवाई गई। अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त विवादित आराजी पर गैरसायलान सं. 1 ल0 10 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि सायलान के 1/5 हिस्से के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न न तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही गयी। सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार होने से अपी0/गैरसायलान के विरुद्ध निर्णय पारित किये जाने से व्यथित होकर अपी0/गैरसायलान द्वारा अपील पेश की गयी है।

2. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पों0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।

3. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिया है कि फैसला अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.12.2019 पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व रिकार्ड के विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अपीलाधीन भूमि ख.नं. 177 रकबा 0.0200, ख.नं. 487 रकबा 0.1400 है0, ख.नं. 493 रकबा 0.8600 है0 कुल रकबा 1.0200 ग्राम पनियाला तहसील मलारना डूंगर में स्थित है जो संयुक्त खातेदारी की भूमि है जो गंगाधर पुत्र कुन्जा 1/5 भाग सोन्या, मोहन पुत्रान कुन्जा 2/5 विलारहन बजरंगा पुत्र कुन्जा 1/5 राहिन सवाई माधोपुर सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा मलारना डूंगर मुर्तहीन बाबू पुत्र कुन्जा हिस्सा 1/5 राहिन बैंक ऑफ बडौदा के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसका विधिवत राजस्व रिकॉर्ड में तकासमा नहीं हुआ है। उक्त भूमि मौखिक बंटवारे के

अनुसार अपी० के हिस्से में आयी है। इसके उपरान्त भी उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी की होते हुए भी अपी० को पाबन्द करने का आदेश अधिनस्थ न्यायालय ने अवैधानिक रूप से पारित किया है जो निरस्तनीय है क्योंकि सहखातेदार को पाबन्द किया जाना कानूनन रूप से अवैधानिक है। सम्पूर्ण अपीलाधीन भूमि पर अपी० का निरन्तर कब्जा काशत चला आ रहा है। अपीलाधीन भूमि मौखिक बंटवारे में अपी० को प्राप्त हुई है तथा अपी० ने उक्त अपीलाधीन भूमि के बदले में अपनी संयुक्त खातेदारी की भूमि में खाता संख्या 4 ख.नं. 188 रकबा 1.3500 है० रेस्पों. सं. 1 को दे दी थी जिसे रेस्पों. सं. 1 काशत कर रहा है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पों. सं. 1 ने इस तथ्य को छिपाया है तथा उक्त एकपक्षीय निर्णय चुपचाप अधिनस्थ न्यायालय से मिलकर पारित करा लिया जो विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपी० के एडवोकेट ने उक्त प्रकरण के बारे में अपी० को कोई जानकारी नहीं दी। दिनांक 14.06.2020 को रेस्पों. सं. 1 अपी० की अपीलाधीन भूमि की जुताई करने गया तो अपी० मुरारी ने उक्त भूमि को जोतने से मना किया तो रेस्पों. सं. 1 ने न्यायालय का स्थगन आदेश बताया। इसके उपरान्त अपी० मुरारी दिनांक 15.06.2020 को अपने एडवोकेट के पास उक्त प्रकरण की जानकारी करने गया तो उक्त स्थगन आदेश की जानकारी हुई तब उसी समय अपी० मुरारी ने नकल हेतु आवेदन कर आदेश की नकल प्राप्त की। इससे पूर्व अपीलाट को उक्त निर्णय की जानकारी नहीं थी। अपी० द्वारा अपील पेश करने तक का समय क्षमा किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा परिसीमन अधिनियम 1963 स्वीकार फरमाया जावें। इस प्रकार उक्त निर्णय का ज्ञान अपीलार्थी को हो सका। अतः अपीलाट की अपील स्वीकार कर, अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जाकर अपील अपीलाट स्वीकार फरमायी जावें।

4. विद्वान रेस्पों० के अभिभाषक ने उपरोक्त तर्कों का प्रतिरोध करते हुए अपील बहस में तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि आराजी खाता सं. 39 ख.नं. 177 रकबा 0.0200 है०, ख. नं. 487 रकबा 0.1400 है०, ख.नं. 493 रकबा 0.8600 है० है जो अपी० व रेस्पों. के संयुक्त खातेदारी की आराजी है जिसमें रेस्पों. सं. 1 का 1/5 हिस्सा है जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है उक्त विवादित आराजी को अपी० व रेस्पों. अपने-अपने हिस्से पर काशत करते चले आ रहे हैं और फसल लाभ ले रहे हैं। दिनांक 07.07.2018 को रेस्पों. सं. 1 अपने हिस्से की आराजी ख.नं. 493 रकबा 0.8600 है० पर फसल काशत कर रहा था तो अपी० व उनके परिवार वाले सभी लोग मौके पर लाठी डण्डे लेकर आ गये और फसल को पलट दिया और रेस्पों. सं. के हिस्से 1/5 पर काशत में माने मजाहमत करने व भविष्य में काशत नहीं करने की धमकी दी। रेस्पों. सं. 1 ने तहसील कार्यालय चलकर खाते छटवाने की बात कही तो अपी० ने साफ इन्कार कर दिया व मारपीट पर आमदा हो गये तथा जान से मारने की धमकी दी। इसकी रिपोर्ट थाना मलारना डूंगर में दर्ज करवाई गई। अधिनस्थ

न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य सबूतों का विधि पूर्वक अध्ययन एवं मनन कर ही अपीलार्थी निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपील को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी होते हुए भी जानबूझ कर अपील देरी से पेश की है। परिसीमन अधिनियम की धारा-5 के बारे में कोई ठोस कारण प्रस्तुत नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमन अधिनियम 1963 खारिज फरमाया जावे। अतः अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे एवं अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

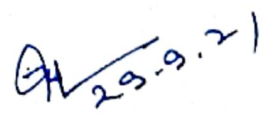
5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया।

6. प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 परिसीमन अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

7. विवादित आराजी सहखातेदारी की आराजी है। अपील द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि रेषों किस हैसियत से सहकाशतकार है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेषों के हिस्से को संरक्षित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पूर्ण विवेचन व विश्लेषण के पश्चात किया गया है इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपील खारिज योग्य है।

8. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपजिला कलेक्टर मलारना डूंगर के मु0नं0 48/2018 निर्णय दिनांक 05.12.2019 को यथावत रखा जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 29.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
( बी0एल0रमण )  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
सवाई माधोपुर